परेशानी

तहसील व एसडीएम कोर्ट में अव्यवस्था का आलम, आम नागरिक परेशान

कोटवार व चपरासी के भरोसे चल रहा सिस्टम!

अनूपपुर,नवभारत 13 अक्टूबर। जिला मुख्यालय स्थित तहसील और एसडीएम न्यायालय में कार्यप्रणाली को लेकर आम नागरिकों, वकीलों और पक्षकारों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि छोटे-छोटे कामों के लिए महीनों चक्कर लगाना पड़ रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी समय पर कोर्ट में नहीं मिलते।

स्थानीय नागरिकों और अधिवक्ताओं ने इस संबंध में कई बिंदुओं पर शिकायत रखी है। इनमें खसरा, खतौनी, आदेश की प्रमाणित नकल के लिए आवेदन करने के बाद हफ्तों तक नकल नहीं मिलती। नागरिकों को बार-बार तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं।



लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समय सीमा में निराकृत नहीं

जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, नामांतरण जैसे लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आने वाले प्रकरण निर्धारित 15 से 30 दिन की समय सीमा में निराकृत नहीं हो रहे हैं। पोर्टल पर पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है।

बिना लेन-देन के काम नहीं होने के आरोप

ग्रामीणों का सबसे बड़ा आरोप है कि बिना रकम लिए कोई जिम्मेदार कर्मचारी काम की जिम्मेदारी नहीं लेता। आदेश शीट में आदेश तक समय पर नहीं लिखा जाता। कोर्ट के चपरासी और बाबू समय पर सीट पर नहीं रहते।

पीठासीन अधिकारी कोर्ट में नहीं बैठते

शिकायत है कि न्यायालयीन समय में पीठासीन अधिकारी अक्सर कोर्ट में नहीं बैठते। कभी निरीक्षण तो कभी बैठक का हवाला देकर कोर्ट खाली रहता है, जिससे दूर-दराज से आए आदिवासी ग्रामीणों को बैरंग लौटना पड़ता है।

छोटे-छोटे प्रकरणों पर हस्ताक्षर से कतराते हैं अधिकारी

अधिवक्ताओं का आरोप है कि छोटे-छोटे आवेदन, शपथ पत्र और प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर करने में तहसीलदार और एसडीएम द्वारा अनावश्यक आनाकानी की जाती है, जिससे गरीब आदमी का काम अटक जाता है। एक ही प्रकरण में बार-बार तारीख देकर वकीलों और पक्षकारों को परेशान किया जाता है। कई प्रकरणों में सालों से सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिससे आम आदमी न्याय के लिए भटक रहा है।

पूरे मामले की जांच करने की मांग

ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों का कहना है कि अंदर की जानकारी के लिए उन्हें कोटवार और चपरासी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अधिकारी से मिलने के लिए भी पहले इन्हीं के जरिए संपर्क करना पड़ता है। इस संबंध में जब पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो कार्यालय में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हुआ। नागरिकों ने कलेक्टर हर्षल पंचोली से इस पूरे मामले की जांच कर व्यवस्था सुधारने की मांग की है।



विद्युत बिल की राशि माफ करने की मांग

कलेक्टर ने जनसुनवाई में 79 आवेदनों पर की सुनवाई

अनूपपुर, नवभारत 13 अक्टूबर। कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में कुल 79 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर त्वरित एवं संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों ने विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए उसका परीक्षण किया जाए तथा पात्रतानुसार निराकरण कर आवेदकों को राहत प्रदान की जाए।

राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने दिया आवेदन

जनसुनवाई में नगर परिषद अमलाई निवासी नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी ने अतिथि शिक्षक वर्ग-2, गणित विषय के पद पर सेवाएं निरंतर जारी रखने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं, ग्राम दुलहरा निवासी कैलाश कोरी ने विद्युत बिल की राशि माफ करने की मांग की। कोतमा के वार्ड क्रमांक 11 निवासी अमृत लाल पटेल ने वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कराने एवं राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया।

नर्मदा परिक्रमा पथ का किया पैदल निरीक्षण

शिवालय घाट से ढाडपाथर तक सीईओ ने किया भ्रमण

अनूपपुर, नवभारत 13 अक्टूबर। जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने जनपद पुष्पराजगढ़ अंतर्गत नर्मदा परिक्रमा पथ का पैदल भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत खेतगांव के शिवालय घाट से ढाडपाथर तक पैदल मार्च कर नर्मदा नदी के किनारों का अवलोकन किया।

इस दौरान परिक्रमा पथ पर आवश्यक सुविधाओं के विकास, पौधारोपण, संकेतक लगाने तथा नदी तटों पर भूमि क्षरण रोकने के लिए विभिन्न स्थलों का चिन्हांकन किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री इंद्रजीत तिवारी, जनपद पुष्पराजगढ़ सीईओ हरिश्चंद्र द्विवेदी, तहसीलदार ईश्वर प्रधान, वीबी-जी राम जी योजना के जिला परियोजना अधिकारी रावेन्द्र पटेल, सहायक कार्यक्रम अधिकारी पुष्पराजगढ़ वरुणेंद्र सिंह बघेल सहित राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।



दिशा-सूचक संकेतक लगाने के दिए निर्देश

जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने ग्राम पंचायत बरांझ, कंचनपुर सहित अन्य ग्रामों का भ्रमण कर नर्मदा परिक्रमा पथ की पुरानी संरचनाओं का जायजा लिया। साथ ही परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए नवीन आश्रय स्थल, पौधरोपण स्थल तथा दिशा-सूचक संकेतक लगाने के लिए उपयुक्त स्थानों का निरीक्षण कर चिन्हांकन किया गया।

जनगणना 2027 : द्वितीय चरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

अनूपपुर, नवभारत। भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों के तहत मंगलवार को जिला पंचायत सभागार अनूपपुर में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को फरवरी 2027 में प्रस्तावित जनसंख्या गणना की प्रक्रिया, प्रशासनिक दायित्वों और तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है। कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देशानुसार आयोजित प्रशिक्षण में भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर एवं प्रभारी जनगणना अधिकारी गिरीश कुमार शुक्ला और महेंद्र यादव ने सीएमएमएस पीई मॉड्यूल, गणना ब्लॉकों के गठन तथा जनगणना की परिचालन प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया।

शंभुधारा क्षेत्र में जर्जर हो रहीं सात ध्यान केन्द्र कुटियां

लाखों की लागत से हुआ था निर्माण, रखरखाव के अभाव में ढहने की कगार पर

अमरकंटक, नवभारत 13 अक्टूबर। मां नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक के शंभुधारा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लाखों रुपये की लागत से निर्मित सात ध्यान केन्द्र इन दिनों बदहाली का शिकार हैं।

नर्मदा परिक्रमा वासियों, श्रद्धालुओं और साधकों को ध्यान, साधना एवं विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गईं ये कुटियां उचित रखरखाव के अभाव में जर्जर होती जा रही हैं। समय रहते मरम्मत और संरक्षण कार्य नहीं हुआ, तो इनके पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। इससे सरकारी धन से विकसित की गई इस सुविधा की उपयोगिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।



ध्यान, साधना और विश्राम के लिए बनाई गई थी

जानकारी के अनुसार शंभुधारा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सात इको-फ्रेंडली ध्यान कुटियों का निर्माण कराया गया था। प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप घास-फूस सहित अन्य प्राकृतिक सामग्री से तैयार इन कुटियों का उद्देश्य श्रद्धालुओं और नर्मदा परिक्रमा करने वाले यात्रियों को प्रकृति के सान्निध्य में ध्यान, साधना और विश्राम के लिए शांत एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराना था।

अलग से बजट उपलब्ध नहीं

बताया जा रहा है कि ध्यान कुटियों की मरम्मत, रंग-रोगन, नियमित देखरेख और आवश्यक श्रमिकों की व्यवस्था के लिए अलग से बजट उपलब्ध नहीं है। वन विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित इस इको-फ्रेंडली ध्यान केंद्र के मरम्मत कार्य के लिए शासन से बजट नहीं मिलने की बात सामने आई है। बजट के अभाव में संरक्षण कार्य प्रभावित होने से कुटियों की हालत और बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।

इनका कहना है

वन विभाग द्वारा पूर्व में इको-फ्रेंडली ध्यान केंद्र बनाया गया था। इसके मरम्मत कार्य के लिए शासन से बजट उपलब्ध नहीं हुआ है। नए ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

वीरेंद्र श्रीवास्तव
वन परिक्षेत्राधिकारी
अमरकंटक

एक नजर में

नगरपालिका में जन-विश्वास अभियान शिविर 16 को

अनूपपुर, नवभारत। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 के तहत आगामी 16 अक्टूबर को नगरपालिका कोतमा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण करेंगे। जिला प्रशासन ने नागरिकों से शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान का लाभ लेने की अपील की है। शिविर के दौरान सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, राशन दुकानों एवं अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा।

जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आज

अनूपपुर, नवभारत। जिला पंचायत अनूपपुर के सभागार में 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति एवं सामान्य सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की डीपीडीपी कार्ययोजना के अनुमोदन के साथ आगामी रबी फसल की तैयारियों और कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की डीपीडीपी कार्ययोजना पर चर्चा कर उसका अनुमोदन किया जाएगा।



रामघाट पर टैक्सी यूनियन ने चलाया स्वच्छता अभियान

अमरकंटक, नवभारत। पवित्र नगरी अमरकंटक को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के उद्देश्य से टैक्सी यूनियन कल्याण समिति, इकाई अमरकंटक द्वारा नवरात्रि के प्रथम दिवस रामघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यूनियन अध्यक्ष आदित्य जायसवाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों और सदस्यों ने श्रमदान कर घाट की सफाई की। अभियान में यूनियन के पदाधिकारियों, सदस्यों, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण उपाध्याय तथा थाना अमरकंटक के आरक्षक कृष्णा राजावत और रवि पटेल सहित अन्य लोगों ने सहभागिता निभाई। इस दौरान अध्यक्ष आदित्य जायसवाल ने प्रशासन से अमरकंटक में संचालित सभी टैक्सियों में डस्टबिन रखना अनिवार्य करने की मांग की।

उदय सिंह ने सुनीं क्षेत्रवासियों की समस्याएं अधिकारियों को दिए निराकरण के निर्देश

समस्याओं का समाधान कराना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य

पसान,नवभारत 13 अक्टूबर। नगर पालिका क्षेत्र पसान के अनूपपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि उदय सिंह ने अपने निवास पर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।

उदय सिंह ने संबंधित अधिकारियों को फोन के माध्यम से समस्याओं की जानकारी देते हुए उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उदय सिंह ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आमजन को राहत दिलाना आवश्यक है।



समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास' भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार का मूल सिद्धांत है। इसी भावना के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहेंगे।



निर्माण कार्यों में देरी और घटिया गुणवत्ता बर्दाश्त नहीं : कलेक्टर

निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

अनूपपुर, नवभारत 13 अक्टूबर। कलेक्टर रत्नाकर झा ने जिले के विभिन्न निर्माण विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।

बैठक में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सहित अन्य विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से लंबित कार्यों और निर्माण में आ रही बाधाओं की जानकारी लेकर उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें

उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के निर्धारित मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और कार्यस्थलों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा। कलेक्टर ने विभागीय समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाने तथा स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

नई पाठ्यपुस्तकों को लेकर शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी

चारों विकासखंडों में 24 मास्टर ट्रेनर तैनात

अनूपपुर, नवभारत 13 अक्टूबर। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशन में जिले में कक्षा सातवीं की नवीन पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है।

12 से 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षकों को नई पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों और विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ विकसित करने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के सुचारु संचालन के लिए जिले के चारों विकासखंडों में छह-छह मास्टर ट्रेनर तैनात किए गए हैं।



अध्यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास

जिला परियोजना समन्वयक संजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई पाठ्यपुस्तकों के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और कक्षा-कक्ष में अध्यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। प्रशिक्षण के लिए अनूपपुर विकासखंड में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जमुना कॉलरी, कोतमा में जनपद शिक्षा केंद्र, पुष्पराजगढ़ में माध्यमिक विद्यालय, राजेंद्रग्राम तथा जैतहरी में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानको केंद्र बनाया गया है।

29 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया

प्रशिक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोतमा विकासखंड में विज्ञान विषय के 18 पंजीकृत शिक्षकों में से 16 उपस्थित रहे, जबकि सामाजिक विज्ञान के 32 में से 29 शिक्षकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। अनूपपुर विकासखंड में विज्ञान विषय के 29 पंजीकृत शिक्षकों में से 28 तथा सामाजिक विज्ञान के 35 में से 34 शिक्षक उपस्थित रहे।

पश्चिम मध्य रेल की माल ढुलाई में 6.36 प्रतिशत वृद्धि

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेल ने चालू वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में माल लदान के मामले में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान कुल 28.84 मिलियन टन माल लदान हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 27.12 मिलियन टन था। मंडलवार आंकड़ों में जबलपुर मंडल 21.86 मिलियन टन के साथ सबसे आगे रहा। भोपाल मंडल ने 3.63 मिलियन टन और कोटा मंडल ने 3.35 मिलियन टन माल लदान किया।

निरीक्षण

ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से की चर्चा ; विभिन्न खदानों का किया निरीक्षण

कोल इंडिया में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाना प्राथमिकता : कोल

जमुना-कोतमा नवभारत 13 अक्टूबर। कोल इंडिया ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह कोल, राष्ट्रीय महामंत्री जय बहादुर सिंह, एसईसीएल ओबीसी संगठन प्रभारी ताराचंद यादव और सिंगरौली से पहुंचे राम मनोहर यादव ने एसईसीएल के जमुना-कोतमा क्षेत्र का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने विभिन्न खदानों का निरीक्षण किया तथा वीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा कर संगठन की गतिविधियों, ओबीसी आरक्षण, कर्मचारियों के हितों और सामाजिक दायित्वों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश के बाद कोल इंडिया में ओबीसी संगठन खड़ा किया गया, ताकि पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों को उचित मंच पर उठाया जा सके।



25 प्रतिशत आरक्षण लागू हो चुका है

उन्होंने कहा कि संगठन की प्राथमिकता कोल इंडिया सहित देश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाना है। उन्होंने एनसीएल में आरक्षण के क्रियान्वयन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके अनुसार वहां 25 प्रतिशत आरक्षण लागू हो चुका है, जबकि निर्धारित 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रयास जारी हैं।

कर्मचारियों के हितों के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे : सिंह

कोल इंडिया ओबीसी संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जय बहादुर सिंह ने कहा कि संगठन का उद्देश्य ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं को एकजुट होकर प्रबंधन और सरकार के सामने रखना है। उउन्होंने कर्मचारियों के हितों, पदोन्नति में आरक्षण, रोजगार के अवसरों और कार्यस्थल पर समान अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाने की बात कही।

सक्रियता से समस्याओं को मिलेगा मंच : यादव

एसईसीएल ओबीसी संगठन के प्रभारी ताराचंद यादव ने कहा कि एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन को सक्रिय और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जमुना-कोतमा क्षेत्र का दौरा भी इसी उद्देश्य से किया गया है, ताकि स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं, उनकी अपेक्षाओं और संगठन की भूमिका को समझा जा सके।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

क्रमांक 818/ प्रवा./तह./2026 — **इश्तेहार** — कोतमा, दिनांक 13/10/2026

पीठासीन अधिकारी-अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

अनूपपुर थर्मल एनर्जी (एम.पी.) प्राईवेट लिमिटेड ..... आवेदक
बनाम
म.प्र. शासन ..... अनावेदक

प्रेषिती :-
आम जनता, तहसील-कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

जरिये इस्तहार सर्वसाधरण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, अनूपपुर थर्मल एनर्जी (एम.पी.) प्राईवेट लिमिटेड द्वारा तहसील-कोतमा अन्तरर्गत स्थित ग्राम-बरबसपुर, जमुड़ी एवं भाठाड़ांड़ की निम्न शासकीय भूमियों पर, मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 25 अगस्त 2017 राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 17 अगस्त 2017 क्रमांक एफ-12/05/2016-सात-शा.2. ए-शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाईप लाईन, केवल या डक्ट बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए भूमि के उपयोक्ता का अधिकार के तहत ग्राम-छतई, माटोलिया एवं उमरदा मे प्रस्तावित 4X800 मेगावाट पावर परियोजना हेतु जल आपूर्ति वावत भूमिगत वाटर पाईप लाईन के निर्माण हेतु वर्णित शासकीय भूमियों मे उपयोक्ता का अधिकार चाहा गया है।

क्रं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा (हे.)	उपयोक्ता के अधीन अर्जन हेतु रकवा (हे.)
1.	बरबसपुर	2	11.7670	0.441
		3	15.1230	0.404
2.	जमुड़ी	2	15.8070	0.057
		227/1	53.913	0.713
3.	भाठाडांड	310/1/1	130.223	0.250
	कुल भूमि हे. में :::		226.863	1.623

तत्संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपना लिखित आपत्ति इस्तहार प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश कर सकते है, म्याद समाप्ति उपरान्त किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। इस्तहार आज दिनांक 13/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कोतमा, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)